भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1303
06 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना
1303. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अगले दो वर्षों के भीतर एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों से अवगत कराने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम, संसाधन या प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में प्राकतिक कृषि को बढ़ावा देने पर विशिष्ट रूप से बल देगी; यदि हां, तो राज्य में इन पद्धतियों को लागू करने की विस्तृत योजनाएं क्या हैं; और

(च) प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में किसानों की सहायता के लिए मौजूद सहायता प्रणालियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): जी हां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को 2481 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.) को मंजूरी दी। इस मिशन का लक्ष्य 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है।

एन.एम.एन.एफ. के तहत किसानों के लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इस मिशन में प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्मों, प्राकृतिक खेती के पद्धति पैकेज, बीजामृत, जीवामृत आदि प्राकृतिक खेती इनपुट तैयार करने, भूमि की तैयारी, नशीजीव एवं रोग प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अभ्यास आदि पर केवीके, कृषि विश्वविद्यालयों, स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों आदि द्वारा प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

एन॰एम॰एन॰एफ में आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना के तहत, इच्छुक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एन॰एम॰एन॰एफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वार्षिक कार्य-योजना प्रस्तुत करनी होती है, ताकि धनराशि रिलीज की जा सके।

किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाने में सहायता करने के लिए एन.एम.एन.एफ. योजना निम्नलिखित सहायता तंत्र उपलब्ध कराएगी:

i. प्रशिक्षण संस्थानों (केवीके, कृषि विश्वविद्यालय, स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थान) के वैज्ञानिकों, किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा लगभग 2000 प्राकृतिक कृषि मॉडल प्रदर्शन फार्मों पर किसानों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ii. प्राकृतिक खेती केंद्रों पर वैज्ञानिकों, किसान मास्टर प्रशिक्षकों, एटीएमए अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों आदि का प्रशिक्षण।

iii. 30,000 कृषि सखियाँ, किसान मास्टर प्रशिक्षकों, प्राकृतिक खेती करने वाले एटीएमए अधिकारियों द्वारा किसानों को निरंतर सहायता प्रदान करना।

iv. 18.75 लाख प्रशिक्षित किसानों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन केवल दो वर्षों के लिए 4000/एकड़/किसान/वर्ष की दर से प्रदान किया गया (वन-टाइम सहायता के रूप में 300 रुपये प्रति माह और 400 रुपये प्रति वर्ष) ताकि वे पशुधन का रखरखाव कर सकें, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आरंभ कर सकें, प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार कर सकें या जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों से खरीद सकें, जागरूकता पैदा कर सकें और प्राकृतिक खेती आरंभ करने के लिए 6 और किसानों को प्रशिक्षित कर सकें।

v. स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक कृषि इनपुट तक आसान पहुंच के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र।

vi. प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए आसान प्रमाणन प्रणाली और राष्ट्रीय साझा ब्रांड, ताकि बाजार तक आसान पहुंच बनाई जा सके।

*****